



P-ISSN: 2706-7483
E-ISSN: 2706-7491
IJGGE 2023; 5(2): 68-70
Received: 03-08-2023
Accepted: 04-10-2023

आर. एन. शर्मा

प्रोफेसर, भूगोल शास्त्र विभाग,
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर,
राजस्थान, भारत।

देवी लाल जाट

शोधार्थी
भूगोल शास्त्र विभाग,
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर,
राजस्थान, भारत।

पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना : एक वरदान

आर. एन. शर्मा, देवी लाल जाट

सारांश

राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यह सम्पूर्ण देश के लगभग 10.41 फिसदी भू-भाग पर विस्तृत है और सम्पूर्ण देश की लगभग 6 फिसदी जनसंख्या यहाँ निवास करती है। यहाँ लगभग 61 प्रतिशत भूभाग पर मरुस्थल फैला हुआ है। कृषि के उत्पादन एवं बागवानी में भी राज्य के किसानों ने नए आयाम खड़े किए हैं। लेकिन बारहमासी नदियों के अभाव के कारण एक बड़ा क्षेत्र अल्प वर्षा वाला होने के कारण राज्य में जल की कमी रहती है। यहाँ के आम जीवन में जल संरक्षण से जुड़ी विधियाँ अटूट रूप से जुड़ी हुई हैं। राजस्थान में समय-समय पर वर्षा की कमी और अनिश्चितता के कारण अकाल तथा सूखे की परिस्थितियाँ बनी रहती हैं। इन्हीं परिस्थितियों का सामना करने के लिए पश्चिम में इंदिरा गांधी नगर की तरफ पूर्वी राजस्थान में भी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की परिकल्पना की गई है। जिससे वर्षा के मौसम में बरसात के जल को नदियों व बांधों में संग्रहित कर उसको जल की कमी वाले क्षेत्रों तक पहुँचा कर राज्य में पर्याप्त पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी। साथ ही कृषि क्षेत्र को भी सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेगी। पूर्वी व दक्षिण पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में सन् 2051 तक पेयजल की आवश्यकता की पूर्ति की जा सकेगी। इस प्रकार यह परियोजना राजस्थान के लिए एक वरदान सिद्ध होगी।

कूटशब्द : परियोजना, मरुस्थल, वारामासी, बागवानी, पेयजल, सिंचाई, प्रौद्योगिकी।

प्रस्तावना

पृथ्वी पर जल की उपस्थिति ही इस ग्रह को अलग बनाती है। जल से ही इस पर जीवन संभव हो पाया है। लेकिन इस ग्रह पर भी जल का समान वितरण नहीं है। किन्हीं क्षेत्रों में जलाधिक्य है तो कहीं पर जल का अभाव है। कहीं पर वर्षा ज्यादा होती है तो कहीं पर वर्षा की मात्रा नगण्य है। इन्हीं विषमताओं को दूर करने के लिए मानव संभववादी विचारधारा के अनुरूप प्रकृति में कांट छांट करता है और अपनी प्रौद्योगिकी का विकास करता है। इसी दिशा में एक कदम राजस्थान सरकार द्वारा उठाया है वह है पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को साकार करना। यह परियोजना राजस्थान की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिससे राजस्थान के अधिशेष जल वाले क्षेत्रों से जल को जलाभाव वाले क्षेत्रों में पहुँचाकर जल संकट को दूर किया जा सके। इस परियोजना के तहत मानसून के दौरान चम्बल नदी की सहायक नदी बेसिनों जैसे कून्नू, कूल, पार्वती, मैज, काली सिंध आदि में उपलब्ध अधिशेष जल को बनास, मोरेल बांध, गम्भीरी में अपवर्तित किया जाना है। इस परियोजना के अन्तर्गत राज्य के पूर्वी भाग के लगभग 2.8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कृषि सिंचाई सुविधायुक्त बनाया जायेगा। साथ ही पेयजल प्राप्ति भी सुनिश्चित की जाएगी। इस परियोजना से राज्य के 13 जिलों की 2051 तक की पेयजल की सुविधा सुनिश्चित की जानी है। एक तरफ जहाँ इंदिरा गांधी नहर परियोजना और नर्मदा नहर परियोजना के प्रयासों से राज्य का उत्तर-पश्चिमी और दक्षिण-पश्चिमी भाग सिंचाई और पेयजल की दृष्टि से सम्पन्न हो रहा है, वहीं राज्य के पूर्वी भाग में इस तरह की कोई बड़ी नहर परियोजना नहीं होने के कारण और धीरे-धीरे भूमिगत जल का स्तर नीचे जाने से पूर्वी राजस्थान में पेयजल व सिंचाई व्यवस्था प्रभावित हुई है। इस वजह से इस बड़े भू-भाग एवं यहाँ निवास करने वाली राज्य की तकरीबन 40 प्रतिशत आबादी के लिए एक प्रमुख सिंचाई एवं पेयजल परियोजना की आवश्यकता समझी गई।

अध्ययन क्षेत्र

राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। जिसका क्षेत्रफल 342.52 लाख हेक्टेयर है जो 23°30' उत्तरी अक्षांश से 30°12' उत्तरी अक्षांश तथा 69°30' पूर्वी देशांतर से 78°17' पूर्वी देशांतर तक स्थित है। राजस्थान राज्य के पूर्वी व दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित 13 जिलों के लिए पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की रूपरेखा बनाई है। 13 जिले इस प्रकार हैं— झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी,

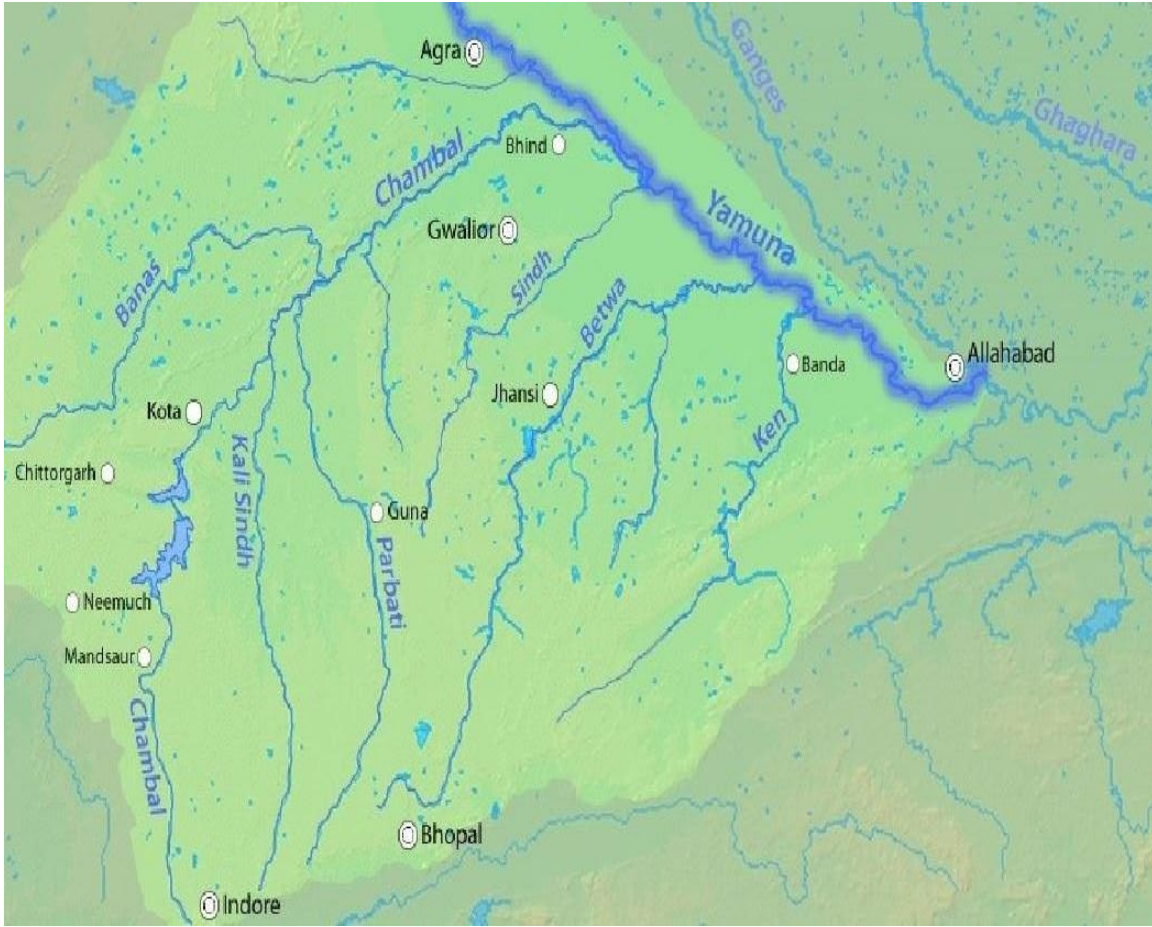
Corresponding Author:

आर. एन. शर्मा

प्रोफेसर, भूगोल शास्त्र विभाग,
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर,
राजस्थान, भारत।

सवाईमाधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, भरतपुर तथा अलवर है। इस सम्पूर्ण परियोजना पूर्वी राजस्थान के लगभग 40000 वर्ग कि.मी. क्षेत्र को कवर करेगी। प्रशासनिक दृष्टि से इस परियोजना क्षेत्र में राज्य के 13 जिले तथा 4 संभागों को सम्मिलित किया गया है। अध्ययन क्षेत्र के 13 जिलों

में से 3 जिलों अलवर, भरतपुर व धौलपुर की सीमाएँ उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा को स्पर्श करती हैं तथा धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां तथा झालावाड़ अर्थात् इन 6 जिलों की सीमाएँ मध्य प्रदेश राज्य की सीमा को स्पर्श करती हैं। अध्ययन क्षेत्र में राज्य की लगभग 39 फिसदी जनसंख्या निवास करती है।



स्रोत: जल संसाधन विभाग, राजस्थान सरकार।

शोध उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन में निम्नलिखित उद्देश्यों को केन्द्र में रखा गया है—

1. पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का भौगोलिक अध्ययन करना।
2. पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के क्रियान्वयन की रूपरेखा का विवरण प्रस्तुत करना।
3. अध्ययन क्षेत्र में जल की कमी की भावी माँग के अनुरूप पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की महत्ता को परिलक्षित करना।

परिकल्पना

शोध शीर्षक "पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना : एक भौगोलिक विश्लेषण" पर निम्नलिखित परिकल्पना है—

इस परियोजना के क्रियान्वयन से अध्ययन क्षेत्र में पेयजल की समस्या का निस्तारण और सिंचाई की अतिरिक्त क्षमता में वृद्धि होगी।

शोध विधि

उक्त अध्ययन में उद्देश्यों एवं परिकल्पनाओं को ध्यान में रखते हुए विषय पर उपलब्ध साहित्य से संबंधित पुस्तकों पत्र-पत्रिकाओं, समाचारों, प्रतिवेदनों का अध्ययन किया गया है। अध्ययन क्षेत्र की सूचनाएँ सरकारी कार्यालयों से एकत्रित करके विश्लेषित की गयी

है। प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु सामग्री तथा आँकड़ों का एकत्रीकरण निम्नलिखित स्रोतों से किया गया है—

1. प्राथमिक स्रोत— इस संबंध में क्षेत्र पर्यवेक्षण, विडियों, फोटोग्राफी तथा व्यक्तिगत भौगोलिक सर्वेक्षण कर अध्ययन सामग्री का संग्रहण किया गया है।
2. द्वितीयक स्रोत— इस संबंध में प्रकाशित एवं अप्रकाशित सामग्री, पत्र-पत्रिकाओं, समाचार पत्रों लेखों, कार्यालय प्रतिवेदनों व सूचनाओं का उपयोग किया गया है।

पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का भौगोलिक अध्ययन

पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) राज्य की एक बड़ी एवं महत्वाकांक्षी सिंचाई परियोजना है जिससे मानसून के दौरान चंबल नदी की सहायक नदी बेसिनों जैसे— कुन्नू, कूल, पार्वती, मैज आदि में उपलब्ध अधिशेष जल को बनास, मोरेल बांध, पार्वती, कालीसिंध, गम्भीरी में अवर्तित किया जायेगा। इस परियोजना के अंतर्गत अधिशेष पानी का अपवर्तन किया जाएगा। इस परियोजना के अन्तर्गत राज्य के पूर्वी भाग के लगभग 2.8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधायुक्त बनाया जायेगा, साथ ही पेयजल प्राप्ति भी सुनिश्चित की जायेगी। इस परियोजना का विस्तार राज्य के 13 जिलों में होगा जिसमें झालावाड़ बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर, जयपुर, दौसा, करौली, अलवर, भरतपुर, धौलपुर जिले सम्मिलित हैं। इन्हें 2051 तक की पेयजल की सुविधा सुनिश्चित की जानी है। इसके साथ पूर्व में

निर्मित 26 बड़ी एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को भी जल प्राप्त होगी। इनमें चाकन (बूंदी), ठीकरिया, कुम्हारिया, गलवा, गलवानिया, मासी, टोरडी सागर, बीसलपुर (टोंक), मालीसिंध, पांचना, जगगर (करौली), जयसमंद (अलवर), पार्वती, रामसागर, तालाबशाही, उर्मिला सागर (धौलपुर, रामगढ़), कालख, कानोता, छपरवाड़ा (जयपुर) बंध बारेठा (भरतपुर) आदि में जल डालकर लगभग 0.80 लाख हैक्टेयर पर सिंचाई सुविधा सुनिश्चित की जायेगी साथ ही 2 लाख हैक्टेयर नवीन क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई पद्धति का विकास होगा। इसके अतिरिक्त डीएमआईसी (दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक गलियारे) के निर्माण तथा औद्योगिक इकाइयों में उपयोग के लिए 286.4 एम.टी. जल उपलब्ध करवाया जायेगा।



स्रोत: जल संसाधन विभाग, राजस्थान सरकार।

ईआरसीपी पूर्वी राजस्थान के चहुंमुखी विकास का आधार बनने की पूर्णरूप से संभावनाएँ हैं। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (स्केच) के अन्तर्गत बांधों का निर्माण कम किया जायेगा और बैराज अधिक बनाए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत 5 बैराज प्रस्तावित हैं। बांध निर्माण करने से एक बड़े क्षेत्र का अधिग्रहण किया जाता है जिसके अन्तर्गत बांध के केचमेंट क्षेत्र के अन्तर्गत सामान्य जनजीवन के पुनर्वास की समस्या उत्पन्न होती है। इसके साथ स्थानीय स्तर पर विकसित आर्थिक क्रियाएँ और गतिविधियाँ भी प्रभावित होती हैं। इस परियोजना के अन्तर्गत 6 बैराज प्रस्तावित हैं। कुनू (56.97 मी.), रामगढ़ (50.49 मी.) महलपुर (162.20 मीटर), बारां। नवनेरा (226 मीटर) कोटा। मेज (50.80 मीटर) बूंदी। राठौड बैराज (143.09 मीटर) सवाई माधोपुर और डूंगरी बांध बनवास नदी पर खण्डार तहसील में सवाई माधोपुर में प्रस्तावित है। इस परियोजना के अन्तर्गत फीडर नहर तंत्र की कुल लम्बाई 1268 कि.मी. प्रस्तावित है जिसकी ग्रेविटी फीडर के अन्तर्गत लम्बाई 965 कि.मी., पम्पिंग मैन की लम्बाई 141 कि.मी. नेचुरल स्ट्रीम की लम्बाई 157.50 कि.मी. है। परियोजना के अन्तर्गत 15 स्टेशनों पर पंपिंग स्टेशन विकसित किए जाएँगे।

परियोजना की मौजूदा स्थिति

इस परियोजना का प्रारूप 2005 में सम्पादिक मध्य प्रदेश-राजस्थान अन्तर्राज्यीय नियंत्रण मण्डल की 13वीं बैठक के अनुरूप ही है, इसलिए यह सुख्याद है कि अब इस परियोजना पर मध्यप्रदेश की अनापत्ति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकार इस परियोजना को लेकर बहुत गम्भीर है। मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार केन्द्र सरकार से लगातार बैठकें एवं पत्र-व्यवहार कर रहे हैं और इस परियोजना की भविष्य में आवश्यकता बताते हुए केन्द्र सरकार से इस परियोजना को

राष्ट्रीय दर्जा देने की माँग कर रहे हैं। राज्य सरकार ने इसके दो महत्वपूर्ण घटक नवनेरा बैराज एवं ईसरदा बांध का कार्य प्रारम्भ कर दिया है और इसकी आधारभूत संरचना विकसित कर दी गई है।

निष्कर्ष

पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का विकास किए जाने से क्षेत्र में आर्थिक-सामाजिक विकास में वृद्धि होगी। साथ ही दिल्ली मुम्बई औद्योगिक गलियारे को जलापूर्ति होने से राज्य में औद्योगिक विकास का मार्ग प्रशस्त होगा एवं रोजगार में वृद्धि होगी। सिंचाई क्षमता बढ़ने से कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी। साथ ही इस परियोजना के विकास में राज्य सरकार को वित्त के अभाव का सामना करना पड़ रहा है जिससे इस योजना का पूर्व विकास नहीं हो पा रहा है इसके लिए केन्द्र सरकार के द्वारा इसे राष्ट्रीय महत्व की परियोजना घोषित कर समयबद्ध रूप से परियोजना को पूर्ण करने की आवश्यकता है।

संदर्भ सूची

1. Water Source Department Rajasthan Govt.
2. Central Water Commission, India Govt.
3. Rajasthan River Basin Authority Rajasthan Govt.
4. Spensur GW, Corder DJ. Water Conservation Handbook, 1971.
5. कथूरिया: Water Shed planning for Optimum Utilization of Water, 1978.
6. हरिमोहन सक्सेना: राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी (राजस्थान का भूगोल)
7. Arora SP. Planning of Rural Water Supply, 2011: Census of India.